Class - B.A-I(H)
paper - I

Lecture - 1

प्रो. खुशबू कुमारी
(Guest Teacher,
dept of Pol. Science)
V.S.J. College, Rajnagar,
Madhubani (LNMU)

Topic - राज्य के कार्य (उदारवाद)

राज्य को मानवीय कल्याण का एक अत्याधिक महत्वपूर्ण साधन माना जा सकता है। मानव समाज के प्रत्येक काल में राज्य का कुछ निर्धारित कार्य रहा है जो कि जनता के कल्याण के लिये किये जाते रहे हैं। समय के साथ राज्य के स्वरूप एवं संगठन में परिवर्तन होते रहे हैं और उसी के अनुरूप उसके कार्य में भी परिवर्तन होते रहे हैं। राज्य के कार्य-क्षेत्र के संबंध में अलग-अलग विचारधाराएँ रही हैं। इनमें है प्रमुख है — उदारवाद, समाजवाद तथा लोककल्याणकारी राज्य।

उदारवाद :— उदारवाद के मूल सिद्धांत निम्नलिखित है —

(i) उदारवादी विचारधारा का सबसे प्रमुख तत्व मानवीय विवेक तथा बुद्धि में आस्था है। इस दृष्टिकोण को अपनाकर वह स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहित करता है।

(ii) उदारवाद इतिहास तथा परम्पराओं जो कि बुद्धिसंगत न हो, का विरोध करता है। इसका विश्वास है कि यदि प्रगति के लिए इतिहास तथा परम्पराओं के प्रति विद्रोह किया जाना आवश्यक हो तो इस प्रकार का विद्रोह अवश्य किया जाना चाहिए।

(iii) उदारवाद के अनुसार मनुष्य जन्म से ही

Scanned with CamScanner

स्वतंत्र उत्पन्न होता है और स्वतंत्रता उसका प्राकृतिक एवं जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के जीवन पर किसी स्वेच्छाचारी सत्ता का नियंत्रण न हो और ऐसा वातावरण हो कि व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार आचरण कर सके।

(iv) उदारवादियों का मूल आधार व्यक्ति है और वे व्यक्ति को लक्ष्य मानकर ही आगे बढ़ते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति का भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक कल्याण, उसकी रचनात्मक शक्तियों का विकास ही सबसे अधिक महत्व पूर्ण चीज है।

(v) उदारवादियों का विश्वास रहा है कि व्यक्ति के कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं जो उन्हें जन्म से ही मिलते हैं। ये अनुल्लंघनीय अधिकार हैं।

(vi) उदारवाद धर्म निरपेक्ष राज्य में विश्वास करता है, जिसके अनुसार राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए राज्य के द्वारा अपने सभी नागरिकों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और धर्म के आधार पर अपने नागरिकों में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए।

(vii) उदारवाद शासकीय स्वेच्छाचारिता

का विरोध करता है और इस बात का प्रति-
पादन करता है कि शासन में व्यक्ति की
नहीं वरन् कानून की प्रधानता होनी चाहिए।

(iii) उदारवादी समाज और राज्य को प्राकृतिक
नहीं वरन् कृत्रिम मानते हैं और उनका विचार
है कि इनका निर्माण व्यक्तियों के द्वारा अपनी
कुछ विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने
के लिए ही किया गया। व्यक्ति अपने
आप में पूर्ण है, समाज और राज्य का
संगठन उनके द्वारा अपनी निश्चित योजना
के अनुसार किया गया है और इन
नये व्यक्तियों को यह अधिकार प्राप्त है
जाना है कि वे समाज और राज्य के
संगठन में अपनी आवश्यकता नुसार संशोधन-
परिवर्तन का कार्य कर सकें।

Khushbu Kumari

Scanned with CamScanner